Non-revision of minimum wages of agricultural workers in Punjab

@3180. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Punjab Government has not revised the minimum wages of agricultural workers, as is done in case of industrial workers;

(b) if so, what are the reasons for not revising the minimum wages of agricultural workers;

(c) whether the above action of the Punjab Government is contrary to the decisions of the State Labour Ministers' Conference held in New Delhi; and

(d) whether it is a fact that the Punjab Khet Mazdoor Union have criticised the Government for not revising the minimum wages?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (d) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के कार्मिकों को उपलब्ध कराई गई सुविधायें

@@ 3181. **कुमारी सईदा खातून :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के कार्मिकों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ;

(ख) क्या उनको रेलवे पास आवास, उनके बच्चों को स्कूल में दाखिले इत्यादि की सुविधाए दी जाती हैं ; और

(ग) यदि नही तो उनकी सेवा को रेलवे विभाग का एक भाग मानते हुए उनको ये सुविधाएं कब तक दिए जाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :

(क) से (ग) सरकारी रेल पुलिस संबंधित राज्य सरकारो के नियंत्रणाधीन कार्य करती है जो उन्हें सुविधाए प्रदान करती है। रेलवे उन्हें निम्नलिखित सुविधाए प्रदान करती है :—

I. यथा-संभव आवास ।

II. ड्यूटी के दौरान यात्रा के लिए ड्यूटी कार्ड पास/चैक पास ।

III. संबंधित राज्य सरकारों के विशेष अनुरोध पर केवल कार्मिको को और न कि उनके परिवार के सदस्यों को, रेल अस्पतालों मे आन्तरिक तथा बाह्य चिकित्सा सुविधा ।

IV. जहा संभव हो रेल टेलीफोन सुविधा ।

V. ड्यूटी के दौरान अधिकारियों को मुख्यालय से बाहर यथा संभव किराया मकान की सुविधा ।

VI. रेल स्कूलों मे उनको, बच्चों के दाखिले के लिए कोई विशष सुविधा नही ।

चूंकि सरकारी रेल पुलिस संबंधित राज्य सरकारो के अधीन काम करती है अत: इस संगठन को रेल का एक अभिन्न अंग मानने का प्रश्न नही उठता ।

Gramin Banks in Andhra Pradesh

3182. SHRI NARAYAN KAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Gramin Banks in Andhra Pradesh are allowing all the State Government benefits to the equated cadres in terms of Section

@ Previously unstarred Question 2092, transferred from the 27th November, 1987

@@ पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 2646, 2 दिसम्बर, 1987 स स्थानांतरित ।